

उत्तराखण्ड को 594.75 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वयय वभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सफारिशों के अनुसार उत्तराखण्ड को 75 करोड़ रुपए के अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक कसित जारी की।

प्रमुख बटि

- गौरतलब है कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान की सफारिश की है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जनि राज्यों को अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान की सफारिश की गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हमिचल प्रदेश, केरल, मणपुर, मेघालय, मज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सकिक्मि, त्रपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिमि बंगाल शामिल हैं।
- सफारिश की गई अनुदान राशा वयय वभाग द्वारा सफारिश किये गए राज्यों को 12 समान मासिक कशितों में जारी की जाएगी।
- इस छठी कसित के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशा बिढकर 43,100.50 करोड़ रुपए हो गई है।
- उत्तराखण्ड को सितंबर 2022 के लिये जारी की गई छठी कसित 75 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को जारी कुल अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडीजी) 3568.50 करोड़ रुपए है।
- उल्लेखनीय है कि संवधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान प्रदान कया जाता है। यह अनुदान राशा राज्यों के अंतरण पश्चात् राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिये वित्त आयोगों की कर्मकि सफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
- इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिये अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और वयय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए कया गया था।